

## लोक अदालत में निपटाए गए बिजली चोरी के 1579 मामले

नई दिल्ली: 15 अक्टूबर, 2012 | बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए आयोजित लोक अदालत में रेकॉर्ड 1579 मामलों का निपटारा किया गया। 12 अदालतों ने दो दिन में इन मामलों का निपटारा किया।

साउथ और वेस्ट दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली लीगल सर्विसेज अर्थोरिटी और बीआरपीएल ने जिला अदालत साकेत में शनिवार और रविवार को लोक अदालत का आयोजन किया था। तमाम अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए 1660 लोग बिजली चोरी से जुड़े अपने मामलों को लेकर लोक अदालत में पहुंचे। 12 अदालतों ने लगातार काम करते हुए, लोक अदालत में आए कुल मामलों के 95 प्रतिशत, यानी 1579 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा कर दिया।

लोक अदालत स्थल पर उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए बीआरपीएल ने 12 हेल्प डेस्क लगाए थे। इन हेल्प डेस्क्स पर पूरी तरह से प्रशिक्षित अधिकारियों को तैनात किया गया था, ताकि एक-एक उपभोक्ता पर ध्यान देकर उन्हें तमाम सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकें। यह पूरी तरह से एक पेपरलेस लोक अदालत थी, जिसमें ए4 साइज के करीब 30 हजार पेपर-शीट्स की बचत हुई। यहां फाइलों व कागजों का इस्तेमाल नहीं किया गया और कंप्यूटरों के माध्यम से ही कामकाज को अंजाम दिया गया।

कठिया लगाकर की जाने वाले बिजली चोरी, और मीटर से छेड़छाड़ कर की जाने वाली बिजली चोरी— दोनों तरह के मामलों का निपटारा किया गया। किसी अदालत में पहले से ही लंबित मामले या फिर, किसी भी अदालत में नहीं चल रहे मामले – दोनों तरह के मामलों पर यहां सुनवाई हुई और तत्काल ही फैसले भी दे दिए गए।

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दिल्ली लीगल सर्विसेज कमिटी –डीएलएसए– के चेयरमैन माननीय न्यायमूर्ति श्री डी मुरुगेसन, डीएलएसए की मेंबर सेकेटरी सुश्री आशा मेनन और डीएलएसए साकेत कोर्ट की सेकेटरी सुश्री वृदा कुमारी के सहयोग व समर्थन की बदौलत इस दिवसीय लोक अदालत इस कदर सफल रहा।

जिन उपभोक्ताओं के बिजली चोरी मामलों का यहां निपटारा किया गया, उन्हें सेटल्ड रकम के भुगतान के लिए दो 15 से 45 दिनों तक का वक्त दिया गया है। उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों को 3-4 किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है। सेटल्ड रकम के भुगतान के तुरंत बाद उपभोक्ताओं को नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी दे दिए जाएंगे।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को युणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।